



जापान का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन “दोआई” निश्चित रूप से बेहद डरावना भी है। गुनमा प्रांत का यह स्टेशन, गर्म चश्मे वाले शहर, मीनाकामी के पास शीमीजू सुरंग में बहुत गहराई में है। शीमीजू कभी जापान की सबसे लम्बी सुरंग हुआ करती थी। वर्ष 1931 में जब यह सुरंग बनी थी तो टोक्यो से नौगाता के बीच की दूरी चार घंटे कम हो गई थी। दोआई स्टेशन से ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों को प्रवेशद्वार से 70 मीटर नीचे गहराई में जाना पड़ता है। इसलिए यह जापान का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कहलाता है। इससे पहले यह उपाधि होकायडो के योशीओका-काइतेई स्टेशन के पास थी, जो 2014 में बंद हो गया। दोआई का डिजाइन बहुत अनूठा है। इसमें दो पृथक सिंगल साइड प्लेटफॉर्म हैं जो अलग-अलग ऊंचाई पर बने हैं। दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म प्रवेशद्वार से कुछ सीढ़ी उतरते ही हैं और उत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनों वाले प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के लिए एक गहरी सुरंग से होकर जाना पड़ता है। यह रास्ता बहुत ठंडा और गुफा जैसा है तथा प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए 486 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो बहुत तेज हवा आती है। इसकी एक और अजीब बात यह है कि, यह एक अनमैन्ड स्टेशन है, अर्थात् यहां टिकट चैक करने तक के लिए कोई कर्मचारी नहीं है। यात्रियों से ज्यादा यहाँ “गोस्ट हंटिंग” के शौकीन पर्यटक आते हैं।

टी.आर.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोप लगाया गया था कि यह कंपनी उपचुनाव के दौरान मुन्नागोडे चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का पैसा बाँटा करती थी।

जी.एस.टी. अधिकारियों ने कथित रूप से कम्पनी के अधिकारियों से कुछ वित्तीय लेन देन के बारे में पूछताछ की और जांच के लिए कम्पनी के बही खाते जब्त कर लिए और कम्पनी के ऑडिटर्स को भी सम्मन भेजा।

कहा जा रहा है कि ये रेड्स राज्य के कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर पर ई.डी. रेड्स के प्रतिकार में डाली गई है, आरोप है कि वे ग्रेनाइट स्केम में लिप्त हैं।

मुन्नागोडे उपचुनाव में भाजपा की कड़ी टक्कर से परेशान टी.आर.एस. नेतृत्व ने पार्टी को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। ताकि भाजपा की प्रोथ पर नियंत्रण लगाया जा सके। मुन्नागोडे विधानसभा उपचुनाव यहां के विकास के राजगोपाल रेड्डी के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की वजह से हुए थे। वे उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी थे।

ऐसे समय में जब भाजपा को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के आगमन स्थल पर में देखा जा रहा है, और इसे टी.आर.एस. का विकल्प माना जा रहा है। इसलिए पार्टी इस अवधारणा को तोड़ने के लिए भाजपा के नेताओं को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस सम्बंध में टी.आर.एस. अपने उन नेताओं को वापस लाने के प्रयास में है जो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। उन्हें सरकार में ऊंचे पद की पेशकश की जा रही है। टी.आर.एस. और भाजपा नेताओं ने इस स्थिति पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।

समझा जाता है कि वार्ता अग्रिम दौर में है। पता चला है कि भाजपा मुख्यालय ने तेलंगाना के अपने वरिष्ठ नेताओं को इन हालात पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया है।

इसी बीच टी.आर.एस. और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि मुख्यमंत्री के.सी.आर. राजनैतिक शिष्टाचार निभाना भी भूल गए हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करने का शिष्टाचार तक नहीं निभाया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री के हैदराबाद आने पर वे उनसे नहीं मिले थे।

प्रेस काउन्सिल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निगमों द्वारा इसे दिये गए विज्ञापनों ने, विज्ञापनों से होने वाली आय के लिहाज से, इसे नौवे स्थान पर उतार दिया है। इस अवधारणा द्वारा पेश किये गये तथ्यात्मक आँकड़ें दर्शाते हैं कि, इसे वर्ष 2020 के प्रथम 10 महीनों तथा वर्ष 2022 के प्रथम सात महीनों में राज्य के डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फार्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स (डी.आई.पी.आर.) से शून्य विज्ञापन प्राप्त हुये, अर्थात् कोई विज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। सन् 2021 में भी, जब पी.सी.आई. ने भेदभाव बरतने के संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, तब कहीं जाकर इसे करीब 10 प्रतिशत जैसी गण्य राशि के ही विज्ञापन जारी किये गये।

जाँच रिपोर्ट में, “भेदभाव पूर्ण तरीके” तथा राज्य सरकार की “मॉडल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी गाइड, 2014” के उल्लंघन को दर्शाने वाले बयान के लिये मुख्यमंत्री पर प्रहार किया गया है। पी.सी.आई. ने राज्य सरकार के इस दावे

‘भारत जोड़ो यात्रा ने “असली” राहुल गांधी को दुनिया के सामने पेश किया है’

जयराम रमेश ने कहा कि, भाजपा ने सोशल मीडिया के मार्फत राहुल गांधी की गलत छवि पेश कर दी थी, अब वही सोशल मीडिया कह रहा है कि, यह राहुल गांधी वो नहीं हैं जैसा 70 दिन पहले थे

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। पिछले 2 महीनों से ज्यादा दिनों से चली आ रही भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की इस यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता समेत ब्लॉक के कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के अनुसार, इस पदयात्रा को जनता के द्वार जाबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इसी बीच आज कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि, इस यात्रा से असली राहुल गांधी जनता के सामने आए हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी के अगुवाई में पूरे देश में की जा रही यात्रा का किसी भी राज्य के चुनाव से कोई संबंध नहीं है और अगर इसके प्रभाव का आंकलन करना है तो यह 2024 के लोकसभा चुनाव में ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कहा कि, राहुल गांधी डेटॉल या फेबिकोल ब्रांड नहीं हैं कि उन्हें फिर से रीब्रांड करना पड़े। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले भाजपा ने उनकी खास छवि बना दी थी, खासकर सोशल मीडिया पर। इसने कभी भी सही राहुल गांधी को चित्रित नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा नए राहुल गांधी को नहीं, असली राहुल गांधी को दिखा रही है।

जयराम रमेश के अनुसार, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि में पूरी तरह से बदलाव आया है। आज मीडिया या सोशल मीडिया में राहुल गांधी वैसे नहीं हैं जो 70 दिन पहले थे। उन्होंने कहा कि 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा का फायदा यह है कि वह (राहुल) बिना किसी बिचौलिए के, लोगों के साथ सीधे संपर्क में हैं। इसका नतीजा यह है कि असली राहुल गांधी सबके सामने हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी कोई ब्रैंड नहीं हैं जिसकी रीब्रैंडिंग करनी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि सामने रखी है, वही असली राहुल गांधी हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी कोई ब्रैंड नहीं हैं जिसकी रीब्रैंडिंग करनी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि सामने रखी है, वही असली राहुल गांधी हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी कोई ब्रैंड नहीं हैं जिसकी रीब्रैंडिंग करनी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि सामने रखी है, वही असली राहुल गांधी हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी कोई ब्रैंड नहीं हैं जिसकी रीब्रैंडिंग करनी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि सामने रखी है, वही असली राहुल गांधी हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी कोई ब्रैंड नहीं हैं जिसकी रीब्रैंडिंग करनी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि सामने रखी है, वही असली राहुल गांधी हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि, राहुल गांधी कोई ब्रैंड नहीं हैं जिसकी रीब्रैंडिंग करनी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की जो छवि सामने रखी है, वही असली राहुल गांधी हैं।

एकल पट्टा प्रकरण में यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल को राहत

जयपुर 15 नवम्बर (कांस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पट्टा प्रकरण में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ए.सी.बी. कोर्ट में चल रही प्रोटैस्ट पिटिशन समेत अन्य आपराधिक कार्रवाई को शांति धारीवाल की हद तक रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, प्रकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, ऐसे में यदि उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी गई तो वह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश शांति धारीवाल की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, एफ.आई.आर में याचिकाकर्ता शांति धारीवाल का नाम नहीं है। नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) के प्रमुख सचिव ने एकल पट्टा की फाइल यूडीएच मंत्री के समक्ष रखी थी, जिसे हाईकोर्ट के आदेश के तहत परीक्षण के बाद वापस विभाग में भेजा गया। वहीं जेडीए ने गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर शैलेन्द्र गर्ग को जारी एकल पट्टा भी निरस्त कर दिया है।

मामले में रामशरण सिंह की शिकायत पर तत्कालीन जौन उपायुक्त ऑंकारमल सैनी, निक्काम दिवाकर, यूडीए के पूर्व सचिव जी.एस. संघु और

दी थी। जिसके आधार पर जेडीए ने 29 जून 2011 को पट्टा जारी किया था, लेकिन पट्टे में रही नुति के कारण 10 मई 2013 को पट्टा निरस्त कर दिया। इसके बावजूद डेढ़ साल बाद एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। एफ.आई.आर., प्रथम और पुरक चार्जशीट के साथ ही पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट में शांति धारीवाल का नाम नहीं था। इसके बावजूद परिव्रादी ने गत 3 जनवरी को प्रोटैस्ट प्रार्थना पत्र पेश कर याचिकाकर्ता को आरोपी बनाने की प्रार्थना की। जिस पर सुनवाई करते हुए

एमेज़ॉन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस नये हमले के अन्तर्गत, ऑर्गनाइज़र ने अपनी कवर स्टोरी में आरोप लगाया है कि “अमेरिकन बैटिस्ट चर्च” (ए.बी.एम.) नामक एक संगठन से कंपनी के वित्तीय संबंध हैं जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में “धर्म-परिवर्तन अभियान” चलाना है। पत्रिका ने आरोप लगाया है कि ए.बी.एम., ऑल इंडिया मिशन (ए.आई.एम.) नामक एक मोर्चा चला रहा है, जिसने पूर्वोत्तर में 25,000 लोगों का धर्मान्तरण करके उन्हें ईसाई बना दिया है। एमेज़ॉन ने इन आरोपों का खण्डन किया है तथा कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एमेज़ॉन इंडिया का ए.आई.एम. या इससे सम्बद्ध संगठनों से कोई संबंध नहीं है।

प्रसंगवश बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के एक संगठन ने नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स” (एन.सी.पी.सी.आर.) के पास शिकायत भेजी थी कि इस सीमावर्ती राज्य में धर्मान्तरण किया जा रहा है। इसके बाद, आयोग ने एमेज़ॉन के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जाँच चला रखी है।

ज्ञानवापी मस्जिद केस में अखिलेश व ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा

नई दिल्ली, 15 नवम्बर। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने ओवैसी और अखिलेश यादव पर केस दर्ज करने की याचिका मंजूर कर ली है। पोषणीयता को लेकर चल रही बहस पर वादी वकील हरिशंकर पांडेय को बड़ी जीत हासिल हुई है। ओवैसी और अखिलेश यादव ने टी.वी. चैनलों पर बयानबाजी की थी।

गौरतलब है कि कोर्ट मंगलवार को दोपहर बाद करीब दो बजे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ज्ञानवापी पर दिए विवादित टिप्पणी के मामले में सुनवाई कर रहा था। इस मामले में पूर्व में भी सुनवाई

वाराणसी की जिला अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि, अखिलेश यादव और ओवैसी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाये। याचिका में कहा गया था कि, दोनों नेताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ टी.वी. चैनल पर बयानबाजियां की थीं, जिससे हिंदुओं की भावनायें आहत हुई हैं।

कहा गया था कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी प्रकरण में अर्नाल टिप्पणी कीं, जिससे हिंदुओं की भावना आहत हुई है। इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो।

अन्ततोगत्वा रिपब्लिकन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोशल मीडिया के माध्यम से हुए ट्रम्प के हमले के बाद से डीसेंटिस ने उनके खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन लगता है कि टिवटर पर डीसेंटिस का मुख्य फोकस तूफान “निकल” से हुई तबाही के बाद ही स्थिति को फिर से व्यवस्थित करने पर है। इस तूफान से फ्लोरिडा के पूर्व तट पर गुरूवार को तबाही मची थी तथा इसे प्रथम श्रेणी का तूफान माना गया था। गवर्नर डोसेंटिस को रीपिड रियॉस डायरेक्टर क्रिस्टिना पुशॉ ने शुक्रवार को टवीट किया कि “तूफान से ध्वस्त हुई सड़क को साढ़े सात घंटे में दुरुस्त कर दिया गया। यदि यहां अभी डेमोक्रेट्स की सरकार होती तो इस काम में महीनों-साल लग जाते। फ्लोरिडा के नेतृत्व का आधार।”

डीसेंटिस ने हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है कि वह वर्ष 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में दौड़ में हिस्सा लेंगे, जबकि ट्रम्प ने फ्लोरिडा बीच स्थित “मार-ए-लागो” रिजॉर्ट से मंगलवार को इसको लेकर एक बड़ी घोषणा की। डिसेंटिस के सहयोगियों को उम्मीद है कि मई माह में होने वाले फ्लोरिडा के विधानसभा सत्र के बाद ही वह वर्ष 2024 को अपनी योजनाओं की घोषणा करेंगे।

रिपब्लिकन्स में डीसेंटिस और ट्रम्प के अलावा जिन नेताओं को राष्ट्रपति चुनाव के संभावित प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, उनमें देश के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निककी हेली और वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन यॉंगकिन शामिल हैं।

मैनपुरी सीट पर भाजपा ने शिवपाल यादव के नजदीकी को टिकट दिया

भाजपा ने उम्मीदवार उतारकर मुकाबला बेहद रोचक कर दिया है

लखनऊ, 15 नवम्बर। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी से रघुराज सिंह शाक्य इस चुनाव में डिंपल के खिलाफ खड़े हुए हैं और वह बुधवार को नामांकन करीगे। ये वही रघुराज हैं, जिन्हें शिवपाल सिंह यादव का करीबी माना जाता है। हैरानी की बात ये भी है कि एक तरफ शिवपाल के करीबी डिंपल के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए हैं, वहीं यू.पी. में सपा ने जो अपने स्टार प्रचारक घोषित किए हैं, उसमें शिवपाल सिंह यादव भी हैं।

मैनपुरी सीट सपा के पूर्व अध्यक्ष व यू.पी. के सी.एम. रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि मुलायम सिंह के सम्मान में भाजपा इस सीट से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी।

लेकिन आखिरी वक्त में भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव समेत अन्य राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मगर

पर नाराजगी भी जलाई थी। पर यह मामला केवल मीडिया को दी गई धमकी का ही नहीं है बल्कि धमकी को अमल में लाने के तरीकों का भी है। क्योंकि राज्य रिर्कों ही रहा है। तब मुख्यमंत्री गहलोत ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा कि “अच्छा है, आप में से कई हैं जो मुझे खुश करना चाहेंगे।” प्रैस काउन्सिल ने मुख्यमंत्री के उक्त बयान के खिलाफ 13 जनवरी, 2020 को स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुति के लिये नोटिस भेजा था।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से पिछले तीन साल में कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री ने मीडिया को धमकी दी थी, बल्कि जब प्रैस काउन्सिल को इन्व्वायरी कमेटी ने सरकार की विज्ञापन नीति और 2020 से जारी किये गये विज्ञापनों का रिर्कॉड मांगा तो तब यह जाहिर हो गया था कि सरकार अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहती और तारीख ले-लेकर मामले को आगे खिसकाना चाहती है। प्रैस काउन्सिल की कमेटी ने कई बार सरकार को तारीख लेने की आदत

पहले तो माना जा रहा था कि, शायद भाजपा मुलायम सिंह के सम्मान में कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। देखना यह है कि, शिवपाल यादव अपने ही बेहद करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य के खिलाफ किस तरह से चुनाव प्रचार करते हैं।

लेकिन आखिरी वक्त में भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव समेत अन्य राज्यों के विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। मगर

पर नाराजगी भी जलाई थी। पर यह मामला केवल मीडिया को दी गई धमकी का ही नहीं है बल्कि धमकी को अमल में लाने के तरीकों का भी है। क्योंकि राज्य रिर्कों ही रहा है। तब मुख्यमंत्री गहलोत ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा कि “अच्छा है, आप में से कई हैं जो मुझे खुश करना चाहेंगे।” प्रैस काउन्सिल ने मुख्यमंत्री के उक्त बयान के खिलाफ 13 जनवरी, 2020 को स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुति के लिये नोटिस भेजा था।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से पिछले तीन साल में कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री ने मीडिया को धमकी दी थी, बल्कि जब प्रैस काउन्सिल को इन्व्वायरी कमेटी ने सरकार की विज्ञापन नीति और 2020 से जारी किये गये विज्ञापनों का रिर्कॉड मांगा तो तब यह जाहिर हो गया था कि सरकार अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहती और तारीख ले-लेकर मामले को आगे खिसकाना चाहती है। प्रैस काउन्सिल की कमेटी ने कई बार सरकार को तारीख लेने की आदत

पूरे देश की निगाह मैनपुरी लोकसभा सीट पर है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने यहां से रघुराज सिंह शाक्य को खास रणनीति के तहत उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वहीं इससे पहले वह 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर इटावा के सदर सीट से सांसद रह चुके हैं। साथ ही 2012 में इटावा के सदर से विधायक रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में फूट पड़ने के बाद वह शिवपाल यादव के साथ हो लिए थे, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य उनके काफी करीबी थे। मगर यू.पी. इलेक्शन 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए। शाक्य मूल रूप से इटावा के निवासी हैं। उनके पिता रामसिंह शाक्य भी पूर्व सांसद रह चुके हैं।

पूरे देश की निगाह मैनपुरी लोकसभा सीट पर है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने यहां से रघुराज सिंह शाक्य को खास रणनीति के तहत उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वहीं इससे पहले वह 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर इटावा के सदर सीट से सांसद रह चुके हैं। साथ ही 2012 में इटावा के सदर से विधायक रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में फूट पड़ने के बाद वह शिवपाल यादव के साथ हो लिए थे, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य उनके काफी करीबी थे। मगर यू.पी. इलेक्शन 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए। शाक्य मूल रूप से इटावा के निवासी हैं। उनके पिता रामसिंह शाक्य भी पूर्व सांसद रह चुके हैं।

पूरे देश की निगाह मैनपुरी लोकसभा सीट पर है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने यहां से रघुराज सिंह शाक्य को खास रणनीति के तहत उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वहीं इससे पहले वह 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर इटावा के सदर सीट से सांसद रह चुके हैं। साथ ही 2012 में इटावा के सदर से विधायक रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में फूट पड़ने के बाद वह शिवपाल यादव के साथ हो लिए थे, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य उनके काफी करीबी थे। मगर यू.पी. इलेक्शन 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए। शाक्य मूल रूप से इटावा के निवासी हैं। उनके पिता रामसिंह शाक्य भी पूर्व सांसद रह चुके हैं।

पूरे देश की निगाह मैनपुरी लोकसभा सीट पर है, जहां से अखिलेश यादव की पत्नी अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने यहां से रघुराज सिंह शाक्य को खास रणनीति के तहत उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वहीं इससे पहले वह 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर इटावा के सदर सीट से सांसद रह चुके हैं। साथ ही 2012 में इटावा के सदर से विधायक रह चुके हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में फूट पड़ने के बाद वह शिवपाल यादव के साथ हो लिए थे, क्योंकि रघुराज सिंह शाक्य उनके काफी करीबी थे। मगर यू.पी. इलेक्शन 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए। शाक्य मूल रूप से इटावा के निवासी हैं। उनके पिता रामसिंह शाक्य भी पूर्व सांसद रह चुके हैं।

सरदारशहर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पोषणा की गई है। पिंचा पर एक बार फिर से भरोसा जताने में दिलचस्प बात यह है कि वह 4 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें विधानसभा चुनावों में हार का सामना कर चुके हैं उन्हें अब छठी बार टिकट दिया जा रहा है। भाजपा के सियासी गलियारों में भी इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। इधर सियासी गलियारों में चर्चा है कि अशोक कुमार पिंचा को प्रत्याशी बनवाने में भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठीड़ और रतनगढ़ से भाजपा विधायक अभिनेष महर्षी की जमकर चली।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी चूरू जिले के राजगढ़ के ही मूल निवासी हैं। बताया जा रहा है कि तीनों नेताओं की सिफारिश पर ही पिंचा पर पार्टी ने फिर एक बार भरोसा जताया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पिंचा पूर्व मुख्यमंत्री वसुधरा राजे के समर्थक हैं। पहले भी राजे ने हारने के बाद भी पिंचा को टिकट दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि संगठन के नेता इस सीट पर किसी जाट या ब्राह्मण पर दाव खेदना चाहते थे, लेकिन अन्तिम में पार्टी की केन्द्रीय विधानसभा ने पिंचा का टिकट दिया। पिंचा ने 1998 में भाजपा के टिकट पर

पहली बार सरदारशहर सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2003, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव पिंचा जीत गए थे। उन्होंने इसमें कांग्रेस प्रत्याशी भंवरलाल शर्मा को हराया था। चौबीस जुलाई 1960 को जन्मे अशोक कुमार पिंचा ने बीकॉम और बीएएमएस की पढ़ाई की है। वह शुरू से ही संघ से जुड़े रहे हैं और आरएसएस और जनसंघ के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं।

अशोक कुमार ने पहली बार 1990 में हुए पालिका के चुनाव में नार्पद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा था। वर्ष 1995 में वह सरदारशहर पालिका में उपाध्यक्ष रहे और उसके बाद उन्होंने 1998 में भाजपा के टिकट पर पहली बार सरदारशहर से विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनकी पत्नी सुषमा पिंचा वर्ष 2015 में सरदारशहर नगर पालिका अध्यक्ष चुनी गई थी। कांग्रेस नेता भंवर लाल शर्मा के निधन के कारण यह विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। वह गद विधानसभा चुनाव में सरदारशहर से विधायक निर्वाचित हुए थे।

‘पी.सी.आई. ‘सैंसर बोर्ड’ नहीं है ...

पी.सी.आई. के आदेश में यह कहा गया कि, विज्ञापन सरकारी अनुदान नहीं हैं, और यह सरकार की मनमानी से नहीं दिए जा सकते। पी.सी.आई. ने यह भी कहा है कि, विज्ञापन जारी करना राजनीतिक प्रतिबद्धता से निर्धारित नहीं हो सकता।

24 मार्च 2021 में राज्य सरकार द्वारा प्रैस काउन्सिल में जवाब दायर किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि पी.सी.आई. का कार्यक्षेत्र केवल न्यूज पर्सियों तथा अखबारों को “सैंसर” करने का है।

सरकार की इस दलील के जवाब में राष्ट्रदूत की ओर से पी.सी.आई. को पत्र लिखा गया और स्पष्ट किया गया कि प्रैस काउन्सिल की स्थापना भारत में प्रैस के स्तर को बेहतर करने और मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिये किया गया था। प्रैस काउन्सिल एक्ट 1978 की धारा 13(1), 13(2)(ए) उल्लेखनीय है कि पी.सी.आई. का गठन 1966 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रैस कमीशन की बैठक के बाद किया गया था। पी.सी.आई. ने 15 नवम्बर को प्रकाशित अपने फैसले में कहा है कि प्रैस काउन्सिल की स्थापना यकीनन देशभर में अखबारों-न्यूज पर्सियों की स्वतंत्रता को बचाने के लिये हुई थी। इस आदेश में आगे कहा कि प्रैस काउन्सिल एक्ट, 1978 के तहत पी.सी.आई. को एसी

किसी भी गतिविधि या नीति पर नजर रखनी होती है जिससे जनहित में जारी न्यूज के प्रसारण और प्रकाशन में बाधा उत्पन्न हो। पी.सी.आई. ने आगे केवल न्यूज पर्सियों तथा अखबारों को “सैंसर” करने का है।

सरकार की इस दलील के जवाब में राष्ट्रदूत की ओर से पी.सी.आई. को पत्र लिखा गया और स्पष्ट किया गया कि प्रैस काउन्सिल की स्थापना भारत में प्रैस के स्तर को बेहतर करने और मीडिया की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिये किया गया था। प्रैस काउन्सिल एक्ट 1978 की धारा 13(1), 13(2)(ए) उल्लेखनीय है कि पी.सी.आई. का गठन 1966 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रैस कमीशन की बैठक के बाद किया गया था। पी.सी.आई. ने 15 नवम्बर को प्रकाशित अपने फैसले में कहा है कि प्रैस काउन्सिल की स्थापना यकीनन देशभर में अखबारों-न्यूज पर्सियों की स्वतंत्रता को बचाने के लिये हुई थी। इस आदेश में आगे कहा कि प्रैस काउन्सिल एक्ट, 1978 के तहत पी.सी.आई. को एसी